RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 159
दि. 08.10.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

'आपके स्वागत के लिए उत्सुक हूं...', पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात, जन्मदिन की दी बधाई

नई दिल्ली, (जीएनएस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की और उन्हें 73वें जन्मदिन की बधाई दी. इस बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत-रूस के विशेष और प्रिविलेजड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को उनके स्वास्थ्य और सभी प्रयासों में सफलता की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि भारत रूस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक सहयोग को और ऊंचाई पर ले जाने का अवसर तलाश रहा है.

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं. यह मुलाकात भारत में आयोजित होने वाले 23वें इंडिया-रूस एनुअल समिट में होगी. ये समिट इसी साल दिसंबर में होना है.

इस समिट के माध्यम से दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तारित करने और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने की योजना बना रहे हैं. पीएम मोदी ने जुलाई 2024 में मॉस्को यात्रा के दौरान पुतिन को भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था.

रूसी राष्ट्रपति ने आखिरी बार 2021 में भारत के दौरे पर आए थे. उन्होंने 21वें वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था.

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडा की प्रगति की समीक्षा भी की. इसमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की दिशा पर चर्चा हुई. भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष और प्रिविलेजड रणनीतिक साझेदारी रही है, और दोनों देश इसे और गहरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं.

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच यह फोन संवाद इस बात का संकेत है कि दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को न केवल बरकरार रखना चाहते हैं, बल्कि उसे और विकसित करने के लिए नए मार्ग खोज रहे हैं. इससे आगामी इंडिया-रूस एनुअल समिट में सहयोग के नए क्षेत्र और संयुक्त पहलाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है.

इस अवसर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट किया कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को सतत और समग्र दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. दोनों नेताओं की यह बातचीत वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

सीएम योगी का दिवाली तोहफा: सफाईकर्मियों के खाते में अब सीधे 16 से 20 हजार, मिलेगा ₹5 लाख का मुफ्त इलाज

वाराणसी , (जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफाईकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है. यह घोषणा उन्होंने वाराणसी के रामकटोरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह के दौरान मंच से की. सीएम योगी ने बताया कि ₹16,000 से ₹20,000 प्रति माह सीधे सफाईकर्मियों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा. साथ ही, सभी सफाईकर्मियों का आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, जिससे वे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे. यह घोषणा सफाईकर्मियों के शोषण को रोकने और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए की गई. इस घोषणा से मौजूद सभी सफाईकर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई.

शोषण रुकेगा, सीधा लाभ मिलेगा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से साफ शब्दों में कहा कि अब कोई भी सफाईकर्मी का शोषण नहीं कर पाएगा. 16 से 20 हजार की राशि सीधे प्रत्येक सफाईकर्मी के बैंक अकाउंट में पहुंचेगी.

उन्होंने कहा कि जो लोग सभी के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी सरकार के स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए. इसी कारण, सभी स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज भी मिलेगा. जीवन में पहली बार इस तरह के सम्मान को पाकर और ऐसी घोषणाएं सुनकर सफाईकर्मी काफी खुश नजर आए.

दीपावली की सार्थक अपील और गुलाब वर्षा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपावली को लेकर एक भावुक अपील भी की. उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली तभी सार्थक है जब पूरे प्रदेश भर के सफाईकर्मियों को मिष्ठान जरूर मिले। हर गरीब के घर में दीपक जलना चाहिए और उसे मिष्ठान का स्वाद भी मिलना चाहिए. सीएम ने कहा कि यही समाज की समरसता है, और उनका काम जोड़ना है, क्योंकि "तोड़ने के लिए पहले से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है."

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री ने श्री वाल्टर रसेल मीड के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की

पीएम श्री मोदी ने आज श्री वाल्टर रसेल मीड के नेतृत्व में विचारकों और व्यापारिक नेतृत्व वाले एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने तथा वैश्विक शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने में उनके योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा: "श्री वाल्टर रसेल मीड के नेतृत्व में अमेरिकी विचारकों और व्यापारिक नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई।

आईआईसीए ने नई दिल्ली में जनजातीय विकास के लिए सीएसआर उत्कृष्टता का लाभ उठाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की

आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ, श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने भारतीय कंपनियों द्वारा सीएसआर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि का उल लेख किया, जो 2 प्रतिशत की सीमा को पार कर गया है और ये सामाजिक कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दशार्ता है

सीएसआर के प्रयास समाज के हर हिस्से तक पहुंचने चाहिए, जिससे समावेशिता और न यायसंगत विकास को बढ़ावा मिले: श्री चंचल कुमार, सचिव, एमडीओएनईआर

(जीएनएस)।

जनजातीय विकास के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) उत्कृष्टता का लाभ उठाने पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन 6 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में हुआ। यह एक दो-दिवसीय कार्यक्रम था। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान-भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)- द्वारा किया गया था।

यह कार्यक्रम द्वितीय वार्षिक सीएसआर दिवस को चिन्हित करने, महात्मा गांधी की जयंती मनाने और जनजातीय विकास के लिए सीएसआर उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएसआर पहलों में गांधीवादी न्यास दर्शन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था।

उद्घाटन समारोह में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुगार्दास उइके और केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा भी उपस्थित थे। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने वाले जीवंत स्टालों का विस्तृत दौरा किया। साथ ही, ट्राइफेड द्वारा समर्थित अखिल भारतीय जनजातीय कारीगरों के एक विशेष प्रतिनिधिमंडल ने भी अपने माल विपणन किया।

प्रधानमंत्री ने सरकार के प्रमुख के रूप में 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में अपनी सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश करते हुए भारत के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। वर्ष 2001 में आज ही के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से अपनी यात्रा का स्मरण करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के लिए उनका निरंतर प्रयास रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री पद की ज़िम्मेदारी बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सौंपी गई थी।

प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि जयंती पर सभी को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।

श्री मोदी ने प्राचीन काल से ही भारतीय समाज और पारिवारिक जीवन पर महर्षि वाल्मीकि के पवित्र और आदर्श विचारों के गहन प्रभाव का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक समरसता पर आधारित महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं आज भी राष्ट्र को प्रेरित और आलोकित करती हैं।.प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा; सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीनकाल से ही हमारे समाज और परिवार पर उनके सात्विक और आदर्श विचारों का गहरा प्रभाव रहा है। सामाजिक समरसता पर आधारित उनके वैचारिक प्रकाशपुंज देशवासियों को सदैव आलोकित करते रहेंगे।'

पराली प्रबंधन पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की नई दिल्ली में हुई संयुक्त बैठक

(जीएनएस)।

पराली प्रबंधन को लेकर आज नई दिल्ली, कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की संयुक्त रूप से अहम बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री मजिंदर सिंह सिरसा वर्चुअली शामिल रहें। बैठक में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने और धान पराली के बेहतर उपयोग सहित किसानों के बीच जागरुकता, वित्तीय सहायता, प्रभावी निगरानी, फसल प्रबंधन व विविधिकरण को लेकर व्यापक चर्चा हुई।

बैठक में सर्वप्रथम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्रियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह को अपने-अपने राज्यों में पराली प्रबंधन की स्थिति से अवगत करवाया साथ ही बताया कि पूरी सक्रियता और सतर्कता के साथ पराली प्रबंधन की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों, कर्मचारियों सहित पूरा विभाग गंभीरतापूर्वक कार्य में जुटा है।

बैठक में हरियाणा के कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में वित्तीय सहायता के माध्यम से किसानों को पराली ना जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका व्यापक असर हुआ है। इससे किसान पराली प्रबंधन के लिए वैकल्पिक उपायों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

राज्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि राज्यों में पराली प्रबंधन को लेकर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन निरंतर प्रयास जरूरी है।

उन्होंने कहा कि किसानों के बीच जनजागरुकता अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए पंचायत और ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों व नोडल अधिकारियों की भी भागीदारी यदि सुनिश्चित की जाए, तो और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में फसल प्रबंधन, सीधी बुवाई, विविधिकरण, राज्यों द्वारा कार्य योजना धनराशि का उचित उपयोग, प्रभावी निगरानी साथ ही साथ लक्ष्यबद्ध रूप से व्यावहारिक योजनाओं के निर्माण को लेकर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न उपायों को अपनाते हुए ठोस रूप से मिलकर काम करने से निश्चित रूप से फलदायी परिणाम अर्जित होंगे।

श्री चौहान ने कृषि मंत्रियों से आग्रह किया कि अपने राज्यों में सीधी वुबाई को प्रोत्साहित करें। उन्होंने खेत में सीधी बुवाई की बात कही है जिसके फलस्वरूप पराली का उचित रूप से प्रबंधन व उपयोग हो पायेगा। श्री चौहान ने कहा कि मैं 12 अक्टूबर को अपने ही खेत से इसकी शुरूआत करूंगा। मैं अपने खेत की धान कटने के बाद सीधे गेंहू की बुवाई करूंगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, केंद्र की तर्ज पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ देने का निर्णय

महंगाई भत्ते में जुलाई-2025 से केंद्र की तर्ज पर बढ़ोतरी करने का मुख्यमंत्री का कर्मचारी हितैषी दृष्टिकोण

छठे तथा सातवें वेतन आयोग का लाभ प्राप्त कर रहे राज्य सेवा, पंचायत सेवा एवं अन्य कर्मचारियों सहित कुल 4.69 लाख कर्मचारियों और 4.82 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का 3 महीने का बकाया एक किस्त में दिया जाएगा

गांधीनगर, 07 अक्टूबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के व्यापक हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए छठे और सातवें वेतन आयोग का लाभ प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2025 से केंद्र की तर्ज पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री के इस कर्मयोगी हितैषी निर्णय के अंतर्गत सातवें वेतन आयोग का लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा किया गया है। वहीं, छठे वेतन आयोग का लाभ प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

इस महंगाई भत्ते की 3 महीने की अर्थात 1 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक की बकाया राशि यानी एरियर का भुगतान एक किस्त में किया जाएगा।

महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य सरकार और पंचायत सेवा के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों सहित कुल 4.69 लाख कर्मयोगियों और लगभग 4.82 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी पेंशनरों को मिलेगा।

इतना ही नहीं, राज्य सरकार इस एरियर के तहत कर्मचारियों को कुल 483.24 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। वहीं, वेतन, भत्ते और पेंशन के लिए वार्षिक अतिरिक्त 1932.92 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी।

उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने राज्यसभा के सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता की

संवाद, विचार-विमर्श, बहस और चर्चा संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं- श्री सी. पी. राधाकृष्णन

संसद सदस्यों से लोक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए शून्यकाल, विशेष उल्लेख और प्रश्नकाल जैसे उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग करने का आग्रह किया

भारत का संविधान और राज्यसभा की नियमावली संसदीय विमर्श की लक्ष्मण रेखा निर्धारित करती है - श्री सी. पी. राधाकृष्णन

उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति ने लक्ष्मण रेखा के भीतर सभी सदस्यों के अधिकारों को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

सदन में हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड का उपयोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए

(जीएनएस)।

माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा के सभी राजनीतिक दलों के सदन नेताओं के साथ अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्रियों सहित सदन के 29 नेताओं का स्वागत करते हुए, सभापति ने उनके पदभार ग्रहण करने पर मिले जबर्दस्त समर्थन और शुभकामना संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी हुई कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अल्प सूचना पर एक साथ एकत्रित हुए।

अपने उद्घाटन वक्तव्य में, सभापति ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यसभा गरिमा, अनुशासन और

मयार्दा के साथ कार्य करे, जिसकी वह हकदार है। उन्होंने रेखांकित किया कि संवाद, विचार-विमर्श, बहस और चर्चा संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं।

सदस्यों को जन सरोकार के मुद्दे उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों पर प्रकाश डालते हुए, सभापति ने शून्यकाल, विशेष उल्लेख और प्रश्नकाल को महत्वपूर्ण साधन बताया, जो सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मुद्दों को उठाने की अनुमति देते हैं।

उन्होंने सदस्यों को याद दिलाया कि भारत का संविधान और राज्यसभा की नियमावली संसदीय विमर्श के लिए मार्गदर्शक ढांचे—लक्ष्मण रेखा—का काम करती है। सभापति ने इस ढांचे के भीतर सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही सदन की पवित्रता बनाए रखने की सभी के साझे दायित्व पर जोर दिया।

उन्होंने सभी सदस्यों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सदन के हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड के समय का उपयोग करने का आग्रह किया।

सम्पादकीय

चुनावी बेला पर बिहार में जनहित के लिए हैं काफी योजनाएं

बिहार में विधानसभा चुनावों की तैयारियां अपने चरम पर हैं। कांटे की टक्कर दिखती है बिहार में, पार्टियों के बीच साधे जा रही सीटों के समीकरण के बीच भारतीय चुनाव आयोग ने एसआईंआर यानि गहन मतदाता पुनरीक्षण के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक बिहार में अब 7.42 करोड़ मतदाता हैं। अब बिहार चुनाव की घोषणा भी हो गईं और 14 नवंबर 2025 को रिजल्ट भी आ जाएगा। पाठकों की जानकारी के लिए बिहार में विधानसभा की वुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन के पास 122 सीटें होना जरूरी है। बिहार में फिलहाल जेडीयू और भारतीय जनता पाटा (भाजपा) के घटक दलों वाली एनडीए सरकार है और आरजेडी के तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रातिपक्ष हैं। विधानसभा में अभी भाजपा के 80 विधायक हैं। आरजेडी के 77, जेडीयू के 45 और कांग्रेस के 19, कम्युनिस्ट पाटा के 11, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) के 4, कम्युनिस्ट पाटा (मार्क्सवादी) के 2, कम्युनिस्ट पाटा आफ इंडिया के दो, ओवैसी की पाटा का एक और 2 निर्दलीय विधायक हैं। सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए जमकर रेविड़यां बांट रही है। कहीं तो बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंच रहे हैं तो कहीं चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम नीतीश वुमार की तरफ से करोड़ों रुपए की योजनाओं की घोषणा हो रही है। महिलाओं के खातों में पैसे देने के बाद पीएम मोदी ने युवाओं के लिए करीब 62 हजार करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की हैं। इनमें बिहार के लिए भी काफी योजनाएं हैं। इन योजनाओं से लगता है कि बिहार चुनाव सत्तारूढ़ वेंद्र की एनडीए सरकार के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है और वेंद्रीय नेतृत्व किसी भी हालत में बिहार खोना नहीं चाहता। इन योजनाओं से लगता है कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश वुमार महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान देकर चुनाव में जीत की संभावनाएं बढ़ाने का प्रायास कर रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।

एसआईंआर, वोट चोरी और संविधान रक्षा इनके प्रामुख मुद्दे हैं। एनडीए की अंदरूनी खींचतान भी चिता का विषय बना हुआ है। इस बार चुनाव में एक नया पैक्टर भी जुड़ गया है। वह है पीके यानि प्राशांत किशोर और उनकी जन सुराज पाटा। पीके ने बिहार में अपने आरोपों से तहलका मचा दिया है।

उनके फिलहाल निशाने पर सत्तारुढ़ एनडीए सरकार के मंत्री हैं। प्राशांत किशोर अपनी जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ खींच रहे हैं। देखना यह होगा कि यह किसकी वोट काटते हैं, एनडीए की या महागठबंधन की? अगर पीके 10-12 सीटें निकाल लेते हैं तो यह किग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। बिहार में इस समय लड़ाईं एनडीए बनाम महागठबंधन बनाम जन सुराज पाटा के बीच दिखती है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन चुनाव पूर्व सव्रेक्षणों पर विश्वास नहीं करता पर जो इन पर यकीन करते हैं उनकी जानकारी के लिए एक ताजा सव्रेक्षण का ब्यौरा दे रहा हूं। नीतीश वुमार, तेजस्वी या प्राशांत किशोर.. बिहार का कौन होगा अगला मुख्यमंत्री नाम के सी-वोटर का ताजा सव्रेक्षण आया है। 2025 में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गईं है। हालिया सी-वोटर सव्रे ने दिखाया है कि तेजस्वी यादव अभी सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि प्राशांत किशोर ने लोकप्रिया में नीतीश वुमार को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। कौन जीत रहा है यह कहना मुश्किल है, कांटे की टक्कर है। एनडीए, इंडिया गठबंधन और प्राशांत की जन सुराज पाटा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले ने लड़ाईं दिलचस्प बना दी है। सवाल यह भी है कि क्या नीतीश वुमार लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर एनडीए की जीत होती है तो क्या भाजपा किसी नए मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करेगी। वहीं विपक्ष अगर जीतती है तो उसका कौन मुख्यमंत्री होगा क्योंकि अभी तक इस विषय पर कांग्रोस ने वुछ खुलकर नहीं बोला है। सी-वोटर सव्रे के अनुसार बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लगभग 35 फीसदी लोगों ने भावी मुख्यमंत्री के रूप में चुना है।

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात की सफल सर्वग्राही विकास यात्रा के 24 वर्षों की सफलता का जश्न मनाने के लिए 'विकास सप्ताह' का प्रारंभ

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, मुख्य सचिव और वरिष्ठ सचिवों एवं पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए मन, वचन और कर्म से तत्पर रहने के साथ ही देश के प्रति समर्पण भाव की सामूहिक 'भारत विकास प्रतिज्ञा'ली

गांधीनगर, 07 अक्टूबर : श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर राज्य की विकास यात्रा को एक नया आयाम दिया था।

उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात की 2001 से 2025 तक की 24 वर्षों की सर्वग्राही वैश्विक विकास यात्रा की सफलता गाथा में जनभागीदारी के साथ 7 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले 'विकास सप्ताह'के जश्न की शुरूआत 'भारत विकास प्रतिज्ञा'से हुई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, मुख्य सचिव और वरिष्ठ सचिवों एवं पदाधिकारियों ने विधानसभा पोडियम में आयोजित सामूहिक प्रतिज्ञा पठन कार्यक्रम में शामिल होकर 'भारत विकास प्रतिज्ञा'ली।

देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प किया है, उसे साकार करने में अपना संपूर्ण योगदान देने के लिए सभी लोगों ने मन, वचन और कर्म से तत्पर रहने के साथ ही देश के प्रति समर्पण भाव की सामूहिक भारत विकास प्रतिज्ञा की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित मंत्रियों और मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी एवं वरिष्ठ सचिवों द्वारा ली गई 'भारत विकास प्रतिज्ञा'इस प्रकार है:-

मैं भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रतिज्ञा करता हूँ कि...

- मैं अपने जीवन के हर पल में देश के लिए समर्पित रहूँगा।
- मैं स्वयं के बारे में सोचने से पहले दूसरों के कल्याण के बारे में विचार करूंगा। मैं देश के सभी संसाधनों का न्यायसंगत एवं सतत उपयोग सुनिश्चित करूंगा। मैं देश के सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए निःस्वार्थ भाव से निरंतर प्रयासरत रहूंगा।
- मैं अपने देश की समृद्ध परंपरा और विरासत पर गर्व अनुभव करूंगा तथा उसे संरक्षित रखने का निरंतर प्रयास करूंगा।
- मैं अपने देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा और उनके संरक्षण में योगदान दूंगा।
- मैं जाति, धर्म या वर्ण के सभी बंधनों से मुक्त होकर, बंधुता और एकता की भावना के साथ अपने देश को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। मैं 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के आदर्श को साकार करने हेतु भारत की एकता और अखंडता की रक्षा में निरंतर प्रयासरत रहूंगा।
- मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए अपने मन, वचन और कर्म से निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा।
- "हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी" के आदर्श को अपनाकर, मैं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान देने का प्रयास करूंगा।
- 'राष्ट्र प्रथम' को अपने जीवन का मूलमंत्र बनाकर, मैं अपने देश के विकास और कल्याण हेतु तन, मन और धन से सतत कार्य करता रहूंगा।

विकास सप्ताह के जश्न के अंतर्गत भारत विकास प्रतिज्ञा ऑनलाइन तरीके से भी ली जा सके, इस उद्देश्य से पोर्टल- https://pledge.mygov.in/bharat-vikas/ शुरू किया गया है। राज्य के नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं और प्रतिज्ञा लेकर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए भारत के पहले एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप- "मुंबई वन" की शुरूआत करेंगे

प्रधानमंत्री 8-9 अक्टूबर को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री मुंबई मेट्रो लाइन-3 के अंतिम चरण का उद्घाटन करेंगे और 37,270 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत से निर्मित संपूर्ण मुंबई मेट्रो लाइन-3 को राष्ट्र को समर्पित करेंगे

प्रारंभ की जा रही परियोजनाओं का मुख्य केंद्र बिंदु: निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है

भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टार्मर भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी और विजन 2035 रोडमैप की समीक्षा करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टार्मर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में मुख्य संबोधन देंगे

जीएफएफ 2025 का विषय: एआई, संवर्धित बुद्धिमत्ता, नवाचार और समावेश द्वारा संचालित

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8-9 अक्टूबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नवी मुंबई पहुंचने के बाद दोपहर लगभग 3 बजे नवनिर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे। इसके पश्चात, लगभग 3:30 बजे प्रधानमंत्री नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और समर्पित भी करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

9 अक्टूबर को सुबह लगभग 10 बजे, प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर की मेजबानी करेंगे। दोपहर लगभग 1:40 बजे, दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में भाग लेंगे। इसके बाद, दोपहर लगभग 2:45 बजे, दोनों प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में

शामिल होंगे। वे फेस्ट में मुख्य संबोधन भी देंगे।

नवी मुंबई में प्रधानमंत्री

भारत को वैश्विक विमानन केंद्र में परिवर्तित करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, प्रधानमंत्री लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) के चरण 1 का उद्घाटन करेंगे।

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत विकसित किया गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में, एनएमआईए, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) के साथ मिलकर कार्य करेगा ताकि भीड़भाड़ कम हो और मुंबई को वैश्विक बहु-हवाई अड्डा प्रणालियों की श्रेणी में शामिल किया जा सके। 1160 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ, दुनिया के सबसे कुशल हवाई अड्डों में से एक के रूप में डिजाइन किया गया यह हवाई अड्डा अंततः वार्षिक 90 मिलियन यात्रियों (एमपीपीए) और 3.25 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभाल सकेगा।

इसकी अनूठी सुविधाओं में एक स्वचालित पीपल मूवर (एपीएम) शामिल है, जो एक परिवहन प्रणाली है जो सभी चार यात्री टर्मिनलों को सुचारू अंतर-टर्मिनल स्थानांतरण के लिए जोड़ेगी, साथ ही एक लैंडसाइड एपीएम भी है जो शहर के बुनियादी ढांचे को जोड़ेगा। स्थायी प्रथाओं के अनुरूप, इस हवाई अड्डे में स्थायी विमानन ईंधन (एसएएफ) के लिए समर्पित भंडारण, लगभग 47 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन और पूरे शहर में सार्वजनिक संपर्क के लिए ईवी बस सेवाएं उपलब्ध होंगी। एनएमआईए देश का पहला हवाई अड्डा भी होगा जो वाटर टैक्सी से जुड़ा होगा।

प्रधानमंत्री आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक फैली मुंबई मेट्रो लाइन-3 के चरण 2बी का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण लगभग 12,200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हुआ है। इसके साथ ही, वह 37,270 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत वाली पूरी मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) राष्ट्र को समर्पित करेंगे, यह शहरी परिवहन परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी।

मुंबई की पहली और एकमात्र पूर्णतः भूमिगत मेट्रो लाइन के रूप में, यह परियोजना मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में आवागमन को नए सिरे से परिभाषित करेगी, तथा लाखों निवासियों के लिए एक तीव्र, अधिक कुशल और आधुनिक परिवहन समाधान प्रदान करेगी।

कफ परेड से आरे जेवीएलआर तक 33.5 किलोमीटर लंबी, 27 स्टेशनों वाली मुंबई मेट्रो लाइन-3 प्रतिदिन 13 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगी। इस परियोजना का अंतिम चरण 2बी, दक्षिण मुंबई के विरासत और सांस्कृतिक जिलों जैसे किला, काला घोड़ा और मरीन ड्राइव तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, साथ ही बॉम्बे उच्च न्यायालय, मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नरीमन पॉइंट सहित प्रमुख प्रशासनिक और वित्तीय केंद्रों तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा।

मेट्रो लाइन-3 को रेलवे, हवाई अड्डों, अन्य मेट्रो लाइनों और मोनोरेल सेवाओं सहित परिवहन के अन्य साधनों के साथ कुशल एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा और महानगरीय क्षेत्र में भीड़-भाड़ कम होगी।

प्रधानमंत्री मेट्रो, मोनोरेल,

प्रधानमंत्री 8 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे

आईएमसी 2025: एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 8 से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा

विषय: "परिवर्तन के लिए नवाचार"- डिजिटल परिवर्तन में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करना

केंद्रित क्षेत्र: 6 जी, क्वांटम संचार, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल नेटवर्क और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम

आईएमसी 2025 में 400 से अधिक कंपनियां, लगभग 7,000 वैश्विक प्रतिनिधि और 150 से अधिक देशों के लगभग 1.5 लाख आगंतुक शामिल होंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8 अक्टूबर 2025 को प्रातः लगभग 9:45 बजे यशोभूमि, नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आईएमसी 2025 का आयोजन 8 से 11 अक्टूबर तक "इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म" विषय के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के लिए नवाचार का लाभ उठाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया जाएगा।

आईएमसी 2025 दूरसंचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करेगा और वैश्विक प्रमुखों, नीति निमार्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों को एक साथ एक मंच पर लाएगा। यह कार्यक्रम ऑप्टिकल संचार, दूरसंचार में सेमीकंडक्टर, क्वांटम संचार, 6जी और धोखाधड़ी जोखिम संकेतक जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा, जो अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी, डिजिटल संप्रभुता, साइबर धोखाधड़ी रोकथाम और वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्व में भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा देशों से 1.5 लाख से ज्यादा आगंतुकों, 7,000 से ज्यादा वैश्विक प्रतिनिधियों और 400 से ज्यादा कंपनियों के भाग लेने की आशा है। 5जी/6जी, एआई, स्मार्ट मोबिलिटी, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में 1,600 से ज्यादा नए उपयोग-मामलों को 100 से ज्यादा सत्रों और 800 से ज्यादा वक्ताओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

आईएमसी 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी बल देता है, जिसमें जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, रूस, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं।

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी ने जैव सुरक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान की साझेदारी के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाया

पांच दिवसीय जैव सुरक्षा कार्यशाला ने सीसीआरएच के वैज्ञानिकों को सशक्त बनाया, सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों में भारत की प्रतिक्रिया में वृद्धि

एमएएचई में नये प्रकार के जैव सुरक्षा प्रशिक्षण ने होम्योपैथी शोधकताओं को उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया

विशेष जैव सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए 14 राज्यों के 30 सीसीआरएच वैज्ञानिकों का चयन

अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सीसीआरएच और एमएएचई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

कार्यशाला ने होम्योपैथी वैज्ञानिकों को संक्रामक रोगों और महामारी के संबंध में प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) ने मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (एमएएचई), मणिपाल की घटक इकाई, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एमआईवी) के सहयोग से 6 से 10 अक्टूबर, 2025 तक एमएएचई परिसर, मणिपाल, कर्नाटक में 'जैव सुरक्षा और प्रकोप सिमुलेशन प्रशिक्षण 2025' शीर्षक पांच दिवसीय आवासीय कार्यशाला शुरू की है।

यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सीसीआरएच के अनुसंधान वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत सटीक रूप से तैयार किया गया है। इस क्षमता-निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य तैयारियों, जैव सुरक्षा प्रथाओं और रोगों के प्रकोप की स्थिति में प्रतिक्रिया की क्षमताओं को बढ़ाना है जिससे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संबंधी पहलों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

सीसीआरएच के अनुसंधान वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण के इस अवसर ने भारत के 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीसीआरएच के 33 संस्थानों/इकाइयों की व्यापक भागीदारी के साथ बड़े स्तर पर रुचि पैदा की है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ओर से किए गए गहन ऑनलाइन मूल्यांकन के बाद इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 30 प्रतिभाशाली अनुसंधान वैज्ञानिकों का चयन किया गया।

गणमान्य व्यक्ति और सीसीआरएच अनुसंधान वैज्ञानिक

एमआईवी के निदेशक डॉ. चिरंजय मुखोपाध्याय ने कार्यशाला में सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों, विषय विशेषज्ञों और प्रशिक्षुओं का स्वागत किया। सीसीआरएच के महानिदेशक डॉ. सुभाष कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में सामर्थ्यवान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण और अनुसंधान वैज्ञानिकों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उभरते संकटों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के उद्देश्य से सीसीआरएच और एमएएचई के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया। उन्होंने संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों से निपटने में होम्योपैथी की क्षमता का उल्लेख किया।

इस दौरान, अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रमुख क्षेत्रों में उपयोगी सहयोग को सुगम बनाने के लिए सीसीआरएच और एमएएचई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया। सीसीआरएच के महानिदेशक डॉ. सुभाष कौशिक और एमएएचई के रजिस्ट्रार डॉ. पी. गिरिधर किनी ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सीसीआरएच और एमएएचई के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान

इसके अतिरिक्त, एमएएचई में स्वास्थ्य विज्ञान के प्रो-वाइस चांसलर डॉ. शरत कुमार राव के. ने अपने मुख्य भाषण में इस प्रशिक्षण के आयोजन के प्रयासों की सराहना की और सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन में एमएएचई की ओर से हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया।

सीसीआरएच में अनुसंधान अधिकारी (होम्योपैथी)/वैज्ञानिक-द्वितीय डॉ. सुहाना पी. अजीस, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. श्रीकांत गोपीनाथन पिल्लई, सहायक प्रोफेसर डॉ. सुधीश एन., और एमआईवी, मणिपाल के व्याख्याता श्री अनुप जयराम इस प्रशिक्षण के समन्वयक थे।

जम्मू-कश्मीर के आपदा प्रभावित किसानों को केंद्र सरकार से मिली राहत

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पीएम-किसान की 21वीं किस्त अग्रिम जारी

जम्मू-कश्मीर के 8.55 लाख किसानों के खातों में सम्मान निधि के 171 करोड़ रु. जमा

कृषि भवन, दिल्ली में सादे समारोह में श्री शिवराज सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हुए शामिल

अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान के तहत 4,052 करोड़ रु. दिए जा चुके- श्री शिवराज सिंह

प्रभावित जनता के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं- श्री शिवराज सिंह

5100 घरों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से 85 करोड़ रु. का बजट भी मंजूर- श्री शिवराज सिंह

मनरेगा के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिनों की मजदूरी दी जाएगी- केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह

आपदा के इस समय में अन्य सभी प्रकार से भी हरसंभव सहायता की जाएगी- श्री शिवराज सिंह

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के

माध्यम से जम्मू-कश्मीर के बाढ़ व भूस्खलन प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त अग्रिम जारी की। इस सादे समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुवेर्दी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, वहीं जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री श्री जावेद अहमद डार, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, किसान कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े। आज की किस्त के तहत लगभग 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जिनमें 85,418 महिला किसान शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान के तहत अब तक कुल 4,052 करोड़ रु. की सहायता दी जा चुकी है।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ और अन्य आपदा से प्रभावित जम्मू-कश्मीर के किसानों के साथ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, हम सभी प्रभावित किसानों व अन्य लोगों को संकट से पार निकालेंगे, इसी कड़ी में एक कदम पीएम-किसान की किस्त की यह राशि बड़ी राहत है, जिससे किसान अपने आवश्यक कार्य कर सकेंगे। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि हम किसी भी किसान को संकट की इस घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 894 किलोमीटर बढ़ेगा

24,634 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज रेल मंत्रालय की 24,634 करोड़ रुपये के परिव्यय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें:

महाराष्ट्र में वर्धा - भुसावल के बीच 314 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 84 किलोमीटर लंबी गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी लाइन

गुजरात और मध्य प्रदेश में 259 किलोमीटर लंबी वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन

और, मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबी इटारसी-भोपाल-बीना चौथी लाइन शामिल हैं

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों में व्याप्त इन चार परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3,633 गांवों, जिनकी जनसंख्या लगभग 85 लाख 84 हजार है, तथा दो आकांक्षी जिलों, विदिशा और राजनांदगांव तक संपर्क बढ़ेगा।

लाइन क्षमता में बढ़ोत्तरी से गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। मल्टी ट्रैकिंग (पटरियों की संख्या बढ़ाना) प्रस्ताव परिचालन सुगम बनाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों का व्यापक विकास होगा, वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके लिए रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार इन परियोजनाओं का उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श द्वारा मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाना है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी।

परियोजना खंड सांची, सतपुड़ा बाघ अभयारण्य, प्रागैतिहासिक मानव जीवन के प्रमाणों और प्राचीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय, हजारा जलप्रपात, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करेगा, जो देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा।

यह कोयला, कंटेनर, सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न, इस्पात आदि वस्तुओं के परिवहन के लिए भी आवश्यक मार्ग है। पटरियों की संख्या बढ़ाए जाने से प्रति वर्ष 78 मिलियन टन की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के कारण यह देश के जलवायु लक्ष्यों और परिचालन लागत कम करने, तेल आयात (28 करोड़ लीटर) में कमी लाने और कार्बन उत्सर्जन 139 करोड़ किलोग्राम कम करने में मदद करेगा, जो छह करोड़ वृक्षारोपण के बराबर है।

आईटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए धारा 69ए और 79(3)(बी) के तहत शक्तियों का विवेकपूर्ण और स्पष्ट प्रयोग जरुरी है: श्री एस कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

79(3)(बी) के तहत मध्यस्थों को जारी किए जाने वाले नोटिस मानकीकृत होने चाहिए और उनमें प्रासंगिक कानूनी प्रावधान, स्पष्टता और एकरूपता जैसे जरुरी तत्व शामिल होने चाहिए, ताकि गैरकानूनी सूचनाओं पर अंकुश लगाया जा सके

मध्यस्थों को दिए जाने वाले नोटिसों को सुव्यवस्थित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने "मध्यस्थ प्लेटफार्मों पर सूचना प्रबंधन" पर कार्यशाला का आयोजन किया

नोटिस प्रारूपों के मानकीकरण, स्पष्टता, एकरूपता और सरकार भर में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्यशाला में विभिन्न विशेषज्ञ एक मंच पर हुए एकत्रित

(जीएनएस)।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के तेजी से विकास के चलते, आईटी मध्यस्थों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी सूचनाओं में वृद्धि हुई है। इन गैरकानूनी सूचनाओं पर लगाम कसने के लिए, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) और आईटी नियम 2021 के नियम 3(1)(डी), संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसी सूचनाओं को हटाने या उन तक पहुँच को अक्षम करने के लिए, आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने का अधिकार देते हैं।

इस बावत, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 7 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में मध्यस्थ प्लेटफॉर्म पर सूचना प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस

कार्यशाला का मकसद प्रतिभागियों को आईटी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के प्रमुख प्रावधानों, खास तौर पर धारा 69ए और 79(3)(बी) और नियम 3(1)(डी) के बारे में संवेदनशील बनाना और जिम्मेदार डिजिटल शासन और प्रभावी सामग्री प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद करना था।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए और 79(3)(बी) के दायरे और उद्देश्य पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि धारा 69ए सरकार को, अपनी कार्यकारी क्षमता में, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए खतरा पैदा करने वाले ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। दूसरी ओर, धारा 79, मध्यस्थों को उनके दायित्वों और अनुपालन न करने की स्थिति में संभावित दायित्व के बारे में सूचित करती है, हांलाकि अंतिम फैसला न्यायपालिका के पास रहता है।

उन्होंने एक उपयुक्त प्रारूप की जरुरत पर भी जोर दिया और कहा कि धारा 79(3)(बी) के तहत, धारा 69ए के समान निर्देश/आदेश वाले नोटिसों से सावधानीपूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रावधानों का दायरा पूरी तरह से अलग है। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षक के रूप में, यथोचित सरकार या उसकी एजेंसी को शक्तियों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, शक्तियों का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि वे न्यायिक जाँच का सामना कर सकें और भारत के संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन भी बना रहे।

अपने स्वागत भाषण में संयुक्त सचिव (साइबर कानून) श्री अजीत कुमार ने फर्जी खबरों, गलत सूचनाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग की वजह से बढ़ती चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नोटिसों में होने वाली कमियाँ, अक्सर न्यायिक चुनौतियों का कारण बनती हैं, लिहाजा उन्हें तैयार करते समय एक व्यापक और मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की जरुरत है।

कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण नोटिस तैयार करने के लिए एक मानकीकृत प्रारूप अपनाने पर सरकारी विभागों के बीच आम सहमति बनाने का भी प्रयास किया गया, जिससे कार्यान्वयन में अधिक स्पष्टता, एकरूपता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।

इस कार्यक्रम में भारतीय अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), विधिक कार्य विभाग (डीओएलए), भारतीय सेना, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विषय विशेषज्ञ तथा विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। सरकार ने सभी हितधारकों से मानकीकृत प्रक्रियाओं का पालन करने और स्पष्टता, एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए नोटिसों में जरुरी तत्वों को शामिल करने की अपील की।

भारतीय नौसेना की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता -'थिंक 2025'अब क्षेत्रीय चयन दौर की ओर बढ़ रही है

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना की प्रश्नोत्तरी झ थिंक 2025 ने रोमांचक एलिमिनेशन राउंड के साथ एक महत्वपूर्ण चरण पूरा किया है। देश के विभिन्न हिस्सों से चयनित 166 टीमें अब 13 और 14 अक्टूबर, 2025 को होने वाले क्षेत्रीय चयन दौर में हिस्सा लेंगी। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले नवंबर 2025 की शुरूआत में एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) में आयोजित होगा।

दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय (एचक्यूएसएनसी) के तत्वावधान में आयोजित यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भारतीय नौसेना की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य देशभर के युवाओं में जिज्ञासा, ज्ञान एवं बौद्धिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है और साथ ही समुद्री

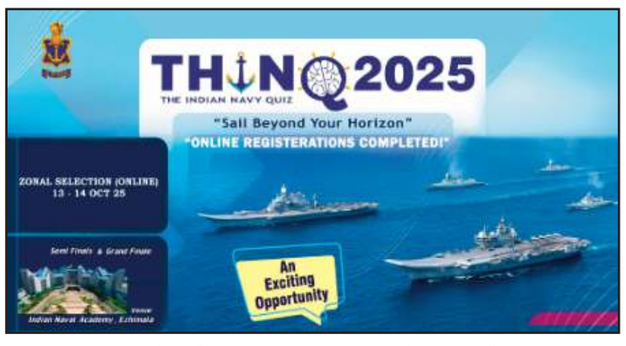

चेतना तथा राष्ट्र के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है।

इस प्रतियोगिता की शुरूआत 08 सितंबर, 2025 को एलिमिनेशन राउंड-क (ईआर-क) से हुई थी, जिसमें देशभर के स्कूलों से उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने इस चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता में अपने संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हुए विविध विषयों पर अपनी जागरूकता, तर्कशक्ति और सामान्य ज्ञान का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

तीन सप्ताह से अधिक समय तक चले एलिमिनेशन राउंड का समापन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों के चयन के साथ हुआ। ये विद्यालय अब 13 और 14 अक्टूबर 2025 को प्रॉक्टर्ड मोड में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय चयन दौर में भाग लेंगे। देशभर से कुल 166 टीमों ने क्षेत्रीय चरण के लिए अर्हता प्राप्त की है।

थिंक न केवल उत्कृष्टता को प्रेरित करने वाले एक सशक्त मंच के रूप में टीम वर्क और प्रतिस्पर्धी भावना को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह प्रतिभागियों में भारतीय नौसेना की गौरवशाली समुद्री विरासत के प्रति आवश्यक जानकारी को फैलाता भी है।

यह पहल युवाओं से जुड़ने, उनमें नेतृत्व क्षमता और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय नौसेना की दृढ़ वचनबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।

यह प्रतियोगिता अब रोमांचक सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले की ओर आगे बढ़ रही है, जो नवंबर 2025 की शुरूआत में एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) में आयोजित होंगे। यहां देश के प्रतिभाशाली युवा प्रश्नोत्तरी थिंक 2025 चैंपियंस के गौरवशाली खिताब के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे।

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 को छात्रों से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने युवा इनोवेटर्स को आत्मनिर्भर भारत के लिए बिल्डथॉन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया

(जीएनएस)।

शिक्षा मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग के सहयोग से विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया है, जिसे छात्रों से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली है और इसमें देश भर के लगभग 2.5 लाख स्कूलों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी छात्र नवाचार पहल है और विकसित भारत के विजन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

इस पहल को बढ़ावा देते हुए, भारतीय वायु सेना के टेस्ट पायलट और इसरो के अंतरिक्ष यात्री तथा विकसित भारत बिल्डथॉन के ब्रांड एंबेसडर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने वीडियो संदेश में छात्रों से इस पहल में शामिल होने और आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने का आग्रह किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिल्डथॉन कक्षा 6-12 के छात्रों को रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हर विचार, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, विकसित भारत 2047 को आकार देने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को अभिनव ढंग से सोचना चाहिए और वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान करने वाले प्रोटोटाइप विकसित करने चाहिए, जिसमें वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी की क्षमता का उपयोग करना शामिल है।

स्कूल फोटो और वीडियो के माध्यम से प्रविष्टियां प्रस्तुत करेंगे, जिनका मूल्यांकन एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा किया जाएगा। शीर्ष पर रहने वाली टीमों को एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

डीआरडीओ ने सैन्य संचार में अंतर-संचालन सक्षमता के लिए भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मानक 1.0 जारी किया

(जीएनएस)।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन-डीआरडीओ ने एकीकृत रक्षा स्टाफ-आईडीएस और तीनों सेनाओं के सहयोग से, 7 अक्टूबर, 2025 को डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान, सैन्य संचार अंतर-संचालन सक्षमता के लिए भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मानक 1.0 औपचारिक रूप से जारी किया। आईआरएसए, सॉफ्टवेयर युक्त रेडियो का व्यापक सॉफ्टवेयर विनिर्देश है, जो मानकीकृत इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, निष्पादन वातावरण और वेवफॉर्म पोर्टेबिलिटी तंत्र को परिभाषित करता है। आईआरएसए को वेवफॉर्म पोर्टेबिलिटी, एसडीआर इंटरऑपरेबिलिटी, प्रमाणन और अनुरूपता के लिए डिजाइन किया गया है। एसडीआर एक वायरलेस संचार प्रणाली है, जो पारंपरिक हार्डवेयर घटकों को सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामेबल प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म से प्रतिस्थापित करती है, जिससे सिग्नल मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन जैसे स्थिति अनुरूप और गतिशील रेडियो फंक्शन संभव होते हैं।

आईआरएसए का शुभारंभ रक्षा संचार प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का निर्णायक कदम है,

जो स्वदेशी, अंतर-संचालनीय और भविष्य के लिए तैयार एसडीआर समाधानों के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देता है। इसे स्वदेशी तौर पर भारत के लिए और वैश्विक प्रयोग हेतु तैयार किया गया है। इसे परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है जो भविष्य की प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करेगा।

कार्यशाला में आईआरएसए की यात्रा, इसके तकनीकी अवलोकन, पारिस्थितिकी तंत्र भूमिकाओं और इसकी भविष्य रूपरेखा पर चर्चा हुई। इसमें उद्योग, शिक्षा जगत और तीनों सेनाओं के सहयोग अवसरों, अग्रिम परियोजनाओं और तकनीक अपनाने के तौर-तरीकों पर विमर्श किया गया।

कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बलों, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और स्वदेशी संचार प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया। डीडी आरएंडडी सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और आईआईटी गांधीनगर के निदेशक डॉ. रजत मूना विशिष्ट अतिथि थे।

आईआरएसए के बारे में:

आधुनिक सैन्य संचार में एसडीआर की महत्वपूर्ण भूमिका और राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर मानक की आवश्यकता पर आईआरएसए पहल 2021 में आरंभ हुई थी। डीआरडीओ के नेतृत्व में एक प्रमुख तकनीकी टीम ने 2022 में एकीकृत रक्षा स्टाफ और सेनाओं के साथ मिलकर परिचालन और उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को समझने के लिए विमर्श आरंभ किया। हितधारकों के साथ व्यापक समीक्षा और परामर्श के बाद, आईआरएसए संस्करण 1.0 को 2025 में उच्च-स्तरीय सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया गया, जो सॉफ्टवेयर युक्त रेडियो के लिए एक मानकीकृत सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर परिभाषित करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय विनिर्देश बना। इसका उद्देश्य आईआरएसए को राष्ट्रीय मानक के साथ ही वैश्विक मानदंड के रूप में स्थापित करना है जिससे भारत एसडीआर की नवीनतम तकनीक विकसित कर मित्र देशों को भी आईआरएसए-अनुरूप समाधान निर्यात कर सके।

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

(जीएनएस)।

भारत के सबसे बड़े छात्र नवाचार आंदोलन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए देश भर के छात्र 11 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग के सहयोग से विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया है। यह देश भर के लगभग ढाई लाख स्कूलों के छात्रों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नवाचार आंदोलन है। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी छात्र नवाचार पहल है और विकसित भारत @2047 के विजन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

छात्र नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता देने के लिए स्कूल अपनी प्रविष्टियाँ फोटो और वीडियो के रूप में प्रस्तुत करेंगे। विशेषज्ञों का एक पैनल प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेगा और शीर्ष टीमों को 1 करोड़ रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मान्यता के अलावा, इन स्कूलों और छात्रों को कॉर्पोरेट स्वीकृति, मार्गदर्शन और

संसाधनों के माध्यम से दीर्घकालिक समर्थन प्राप्त होगा ताकि उनके नवाचारों को और मजबूत किया जा सके।

बिल्डथॉन की मुख्य विशेषताएँ:

डुदेश भर के छात्र दुनिया की सबसे बड़ी लाइव नवाचार गतिविधि में एक साथ नवाचार करेंगे

डुराष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप व्यावहारिक, अनुभवात्मक शिक्षा

डुआकांक्षी ज़िलों, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ समावेशी भागीदारी

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 छात्रों को बड़े सपने देखने, निडर होकर नवाचार करने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में योगदान देने का आ'ान करता है। प्रत्येक स्कूल और प्रत्येक छात्र को इस आंदोलन में शामिल होने और अपनी प्रतिभा दिखाने तथा भविष्य के नवप्रवर्तकों के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

बिल्डथॉन कक्षा 6 से 12 के छात्रों से टीमों में शामिल होने, रचनात्मक रूप से सोचने और वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान करने वाले प्रतिमान विकसित करने का आ'ान करता है। छात्र राष्ट्रीय महत्व के चार विषयों पर काम करेंगे:

रक्षा और सुरक्षा पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है और रक्षा सेक्टर को सुदृढ़ करना केवल एक संस्थान या सरकार का कर्तव्य नहीं, बल्कि सभी भारतीयों का साझा संकल्प है: रक्षा मंत्री

रक्षा में आत्मनिर्भरता हमारे लिए केवल उत्पादन या अर्थव्यवस्था का मामला नहीं, यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हमारी रणनीतिक स्वायत्तता का मामला है और यह सीधे हमारी संप्रभुता से जुड़ा हुआ है

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी रक्षा विनिर्माण इको-सिस्टम के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने की अपील की

'मंत्रालय निवेश, प्रौद्योगिकी अवशोषण और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डीएपी 2020, डीपीएम 2025, रक्षा ऑफसेट नीति और रक्षा निवेशक सेल जैसे ढांचे को लगातार परिष्कृत कर रहा है'

चाहे वह आईडेक्स पहल हो, रक्षा गलियारों की स्थापना हो या रक्षा विनिर्माण में एफडीआई को बढ़ावा देना हो, सरकार ने स्वदेशीकरण की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं: रक्षा मंत्री

भारत का लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये का रक्षा विनिर्माण और 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात अर्जित करना है: रक्षा मंत्री

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 07 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कहा, "रक्षा और सुरक्षा पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है और रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना केवल एक संस्थान या सरकार का कर्तव्य नहीं है, बल्कि सभी भारतीयों का साझा संकल्प है।" 'देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर' विषय पर आयोजित कार्यक्रम के तहत, रक्षा मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक मजबूत, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी रक्षा विनिर्माण इको-सिस्टम के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने की अपील की।

श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारे लिए सिर्फ. उत्पादन या अर्थव्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता का मामला है और सीधे तौर पर संप्रभुता से जुड़ा है। उन्होंने रेखांकित किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब देश को मॉक ड्रिल की जरूरत थी, सभी राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा, "यह सब इस बात का प्रमाण है कि जब हम सभी मिलकर किसी लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।"

भारत का बढ़ता रक्षा उद्योग

रक्षा मंत्री ने पिछले दशक में भारत के रक्षा विनिर्माण सैक्टर की अभूतपूर्व वृद्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन, जो 2014 में 46,000 करोड़ रुपये से अधिक था, अब 2025 में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि 33,000 करोड़ रुपये से अधिक निजी क्षेत्र से आता है, जो स्पष्ट संकेत है कि उद्योग आत्मनिर्भरता मिशन में एक समान हितधारक बन गया है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2014 में 1,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में रिकॉर्ड 23,500 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने रेखांकित किया, "रक्षा उपकरणों के विश्व के सबसे बड़े आयातकों में से एक होने से लेकर रक्षा प्रणालियों के एक विश्वसनीय निर्यातक बनने तक की यह उल्लेखनीय यात्रा हमारे राष्ट्रीय संकल्प का प्रमाण है।"

2029 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य: आत्मनिर्भर भारत की तेज गति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन की पुष्टि करते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये का रक्षा विनिर्माण और 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात अर्जित करना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल मेक इन इंडिया या निर्यात के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस आत्मविश्वास का विषय है कि संकट के समय में हम अपनी रक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, "यह हमारे लिए आत्मविश्वास की बात है कि हमारे सशस्त्र बल जिन अस्त्रों का उपयोग करते हैं, वे हमारी अपनी धरती पर निर्मित हैं और हमारे अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रतिभा से सृजित हैं।"

राज्य नीतियों का संग्रह जारी

रक्षा मंत्री ने रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण पर राज्य नीतियों का एक संग्रह जारी किया, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई नीतियों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का समावेश है। श्री राजनाथ सिंह ने इस दस्तावेज को केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर नीतिगत संयोजन और समन्वय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा, "यह संकलन उद्योग जगत और नवप्रवर्तकों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। मैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह करता हूँ कि वे इसका गहराई से अध्ययन करें, इसकी खूबियों को समझें और रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को लागू करें।" उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज रक्षा निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग को बढ़ावा देगा।

पद्मश्री डॉ. गणपत पटेल की सफलता गाथा : साधारण शुरूआत से विश्वस्तरीय उद्योगपति और शिक्षा क्षेत्र के एक दूरदर्शी नेता तक का सफर

गणपत यूनिवर्सिटी में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन से पद्मश्री डॉ. गणपत पटेल की समृद्ध विरासत उजागर होगी

गांधीनगर, 07 अक्टूबर : उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले के भुणाव गांव में एक साधारण शुरूआत से लेकर कैलिफोर्निया में अध्ययन तक डॉ. गणपत पटेल की सफलता गाथा प्रेरणादायी है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉ. गणपत पटेल ने शिक्षा क्षेत्र में अपने स्वप्न को साकार करने के लिए 'गणपत यूनिवर्सिटी'की स्थापना की। वे एक दूरदर्शी नेता हैं, जो अपने बहुमूल्य योगदान से समाज को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

गणपत यूनिवर्सिटी में वीजीआरसी का आयोजन

राज्य सरकार की नई पहल के रूप में उत्तर गुजरात क्षेत्र के लिए 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस'(वीजीआरसी) का आयोजन मेहसाणा की गणपत यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। गणपत यूनिवर्सिटी नवाचार का एक प्रतिष्ठित केंद्र है। इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के अग्रणी महानुभाव एक साथ, एक मंच पर इकट्ठे होंगे और सेमिनार एवं पैनल चचाओं के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

उत्कृष्टता का सफर

12 जनवरी, 1945 को मेहसाणा के भुणाव गांव में जन्मे डॉ. पटेल ने अपनी शिक्षा की शुरात गांव के प्राथमिक स्कूल की। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद के एम.जी. साइंस

कॉलेज में पढ़ाई पूरी की और इंजीनिरिंग की उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। वहां उन्होंने आईयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी और बाद में 1969 में कैलिफोर्निया की पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, पोमोना से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की।

डॉ. पटेल को मिले सम्मान और उनके मूल्य

डॉ. पटेल को शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2019 में साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा, उन्हें अमेरिका की 'अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन'की ओर से लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड और काल पोली यूनिवर्सिटी, पोमोओ की ओर से 2018 में डिस्टिंग्विश एलुमनस अवॉर्ड से नवाजा गया।

डॉ. पटेल ने अपने करियर की शुरूआत डिजाइन इंजीनियर के रूप में की और अमेरिका की कई अग्रणी कंपनियों के साथ कार्य किया, जिनमें यूएस एविएशन इंडस्ट्री, लॉकहीड (अजूजा), कल्वर सिटी में एबोट ट्रांजिस्टर लैब और जानी मानी कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बरोज कॉर्पोरेशन शामिल हैं। हालांकि, उनका स्वप्न एक उद्यमी बनने का था। 1978 में उन्होंने चेरोकी इंटरनेशनल की स्थापना की, जो आगे चलकर एक सफल वैश्विक कंपनी बनी। फिर 2004 में उन्होंने इस कंपनी को जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) को बेच दिया। शिक्षा के स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने 2005 में 'गणपत यूनिवर्सिटी'की स्थापना की, ताकि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके।

आज, गणवत यूनिवर्सिटी उनके विजन और समर्पण का प्रतीक बन गई है। यूनिवर्सिटी का परिसर 300 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, नवाचार केंद्र, डिजिटल कक्षाएं और पर्यावरण-अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। गुजरात सरकार ने इसे उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में मान्यता दी है, साथ ही इसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) से 'ए'ग्रेड और क्वाक्वेरेली साइमंड्स- क्यूएस आई-जीएयूजीई की ओर से डायमंड रेटिंग भी प्राप्त है।

गणपत यूनिवर्सिटी माननीय प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत@2047'के विजन और गुजरात सरकार के ज्ञान-आधारित, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य का समर्थन करती है। आज के उद्योगों के लिए प्रशिक्षण और नए कौशल प्रदान करने के लिए यूनिवर्सिटी विभिन्न सेक्टर स्कूल काउंसिल और एनएसडीसी इंटरनेशनल के साथ निकटता से जुड़कर कार्य कर रही है। यूनिवर्सिटी ने टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एलान्फोचिप्स, टीसीएस, बॉश रेक्सरोथ, बजाज ऑटो और एमक्योर फार्मा जैसी कंपनियों के साथ गहन साझेदारी की है, जिसके चलते विद्यार्थियों को उद्योगों से संबंधित वास्तविक अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है।

गणपत यूनिवर्सिटी गुजरात का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो मरीन इंजीनियरिंग में बी.टेक. और नॉटिकल साइंस में बीएससी जैसे मैरीटाइम कार्यक्रमों की पेशकश करता है।

विकासशील देशों के शोधकताओं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके प्रभाव पर शोध संगोष्ठी के लिए पोस्टर प्रस्तुत करने को कहा गया, इसका आयोजन भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के साथ किया जाएगा

पोस्टर 31 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं

सबके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भलाई के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विश्व के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भारतीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु अनुसंधान, नीति और व्यवहार समेकन पर संगोष्ठी।

(जीएनएस)।

19 और 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता-एआई और उसके प्रभाव पर 18 फरवरी 2026 को शोध संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। संगोष्ठी में भारत, विकासशील देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख शोधकर्ता और व्यवसायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव पर अपने शोध कार्य प्रस्तुत करने, विधियों और साक्ष्यों के आदान-प्रदान और अनुसंधान, नीति और व्यवहार में सहयोग के लिए एकत्रित होंगे। भारत सरकार ने सम्मेलन की औपचारिक घोषणा 18 सितंबर 2025 को की थी।

कार्यक्रम

पूर्ण सत्रः प्रभावी, दायित्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एजेंडा निर्धारित करने हेतु जाने-माने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकताओं के बीच उच्च स्तरीय वार्ता।

अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रदर्शनीः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान नेतृत्व प्रदर्शित करने वाले पोर्टफोलियो के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त विद्वानों के बीच लघु वार्ता।

विकासशील देश शोकेस (ओपन कॉल): भारत सहित विकासशील देशों विशेष रूप से छात्रों और सहयोगी समूहों द्वारा द्वारा नवीन अनुसंधान दशार्न वाली पोस्टर प्रस्तुतियां।

विकासशील देशों के शोधकताओं के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित

विकासशील देशों के शोधकर्ता जिनके शोधपत्र 2024 या 2025 में अग्रणी एआई सम्मेलनों में प्रकाशित हुए हैं, उन्हें पोस्टर प्रस्ताव (सार+पेपर लिंक) प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः 31 अक्टूबर 2025 (सबमिशन पोर्टल)

स्वीकृति की अधिसूचनाः 15 दिसंबर 2025

अंतिम रूप से पोस्टर प्रस्तुत करनाः 5 जनवरी 2026

संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश impact.indiaai.gov.in/research-symposium पर उपलब्ध हैंः

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अपर सचिव, भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्य कार्यकारी और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र - एनआईसी के महानिदेशक श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि शोध संगोष्ठी अनुसंधान, नीति और व्यवहार के बीच सेतु का काम करेगी। यह विविध दृष्टिकोणों को साथ लाकर ऐसी क्रियाशील अंतर्दृष्टि को आकार देने में सहायक होगी, जो भारत के सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विश्व के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दृष्टिकोण के अनुरूप हो।

आईआईआईटी हैदराबाद के प्रो. पी.जे. नारायणन ने कहा कि शोध संगोष्ठी वैश्विक और भारतीय शोध प्रणेताओं को अपने कार्य साझा करने और भविष्य की साझेदारियां बनाने का अवसर प्रदान करेगी। भारत का जीवंत, समावेशी अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र दायित्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संवाद आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। यह संगोष्ठी इस दिशा में अहम होगी।

भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में यह संगोष्ठी फरवरी 2026 में संपन्न होगी, जिसमें शोध विचार-विमर्श, सम्मेलन की उच्च-स्तरीय नीतिगत वार्ता के साथ समेकित होगा। ये मंच मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ऐसा सहयोगात्मक भविष्य रोडमैप प्रदान करेंगे जो दायित्वपूर्ण, समावेशी और प्रभावी हो।

इंडियाएआई ने डीपफेक का पता लगाने, पूर्वाग्रह में कमी लाने और एआई की बढ़ती पैठ के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक समाधानों के साथ सुरक्षित एआई प्रयासों में वृद्धि की

भारत में सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के अनुकूल परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए पांच क्रांतिकारी प्रस्तावों का चयन किया गया

'साक्ष्य', 'एआई विशेषक' और आईआईटी खड़गपुर की वाणी पहचान प्रणाली भारत की एआई फोरेंसिक व्यवस्था और सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी

डिजिटल फ्यूचर्स लैब और कार्य कृषि से संबंधित एआई अनुप्रयोगों में लैंगिक पूर्वाग्रह से निपटेंगे; ग्लोबल्स आईटीईएस और आईआईआईटी धारवाड़ जनरेटिव एआई सुरक्षा के लिए उपकरण विकसित करेंगे

(जीएनएस)।

एआई प्रौद्योगिकियां जिस प्रकार से अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही हैं उस तरह से उनका सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय उपयोग सुनिश्चित करना राष्ट्र के लिए अनिवार्य बन गया है। भारत स्वदेशी शासन उपकरण, ढांचे और दिशानिर्देश विकसित करने के उद्देश्य से ऐसे चुस्त और मजबूत तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जिनमें देश के अद्वितीय सामाजिक-तकनीकी संदर्भ की झलक मिले।

इंडियाएआई ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिसंबर, 2024 को कई महत्वपूर्ण विषयों पर 'सुरक्षित और विश्वसनीय एआई' स्तंभ के तहत रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का दूसरा दौर शुरू किया था।

इसके अंतर्गत प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्ट-अप्स, अनुसंधान संगठनों और नागरिक समाज से 400 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों की एक समिति का गठन किया गया। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न विषयों पर 5 परियोजनाओं का चयन किया गया। ये परियोजनाएं सामूहिक रूप से सामर्थ्य के परीक्षण और पूर्वाग्रह की जांच को जोड़कर "सुरक्षित और विश्वसनीय एआई" को व्यवहार में लाएंगी ताकि एआई के ज़िम्मेदारी के साथ विकास और उसे उपयोग में लाने में सहायता मिल सके।

भारत एआई मिशन के सुरक्षित और विश्वसनीय एआई स्तंभ में दूसरे ईओआई के तहत चयनित परियोजनाओं की सूची

विषय

परियोजना का शीर्षक

चयनित आवेदक

डीपफेक डिटेक्शन टूल

साक्ष्यः डीपफेक का पता लगाने और शासन के लिए मल्टी-एजेंट, आरएजी-एन्हांस्ड फ्रेमवर्क

आईआईटी जोधपुर (सीआई) और आईआईटी मद्रास

एआई विश्लेषकः प्रतिकूल परिस्थितियों में मजबूती, व्याख्यात्मकता और डोमेन सामान्यीकरण के साथ ऑडियो-विजुअल डीपफेक का पता लगाने और हस्तलिखित हस्ताक्षर की जालसाजी का पता लगाने में सुधार

आईआईटी मंडी और फोरेंसिक सेवा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

रीयल-टाइम वॉयस डीपफेक डिटेक्शन सिस्टम

आईआईटी खड़गपुर

पूर्वाग्रह में कमी लाने की व्यवस्था

कृषि एलएलएम में लैंगिक पूर्वाग्रह का मूल्यांकन - बेंचमार्किंग और निष्पक्ष डेटा कार्य के लिए डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं (डीपीजी) का निर्माण

डिजिटल फ्यूचर्स लैब और कार्या

प्रवेश परीक्षण और मूल्यांकन

एनविलः एलएलएम और जनरेटिव एआई के लिए पेनेट्रेशन टेस्टिंग और मूल्यांकन उपकरण

ग्लोबल्स आईटीईएस प्राइवेट लिमिटेड और आईआईआईटी धारवाड़

रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के दूसरे दौर के अंतर्गत चयनित पांच परियोजनाएं सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के दृष्टिकोण को ठोस समाधानों में बदलने के लिए इंडियाएआई की प्रतिबद्धता को दशार्ती हैं। इस प्रकार की पहलें डीपफेक की वास्तविक समय में पहचान को बढ़ावा देंगी, फोरेंसिक विश्लेषण को मजबूत करेंगी, एआई मॉडलों में पूर्वाग्रहों को दूर करेंगी और जनरेटिव एआई के लिए मजबूत मूल्यांकन उपकरण तैयार करेंगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत में उपयोग में लाई जाने वाली एआई प्रणालियां विश्वसनीय, सुरक्षित और समावेशी हों। इंडियाएआई मिशन अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग भागीदारों और नागरिक समाज को एक साथ लाकर नवाचार, नैतिक प्रथाओं और एआई के लिए सामर्थ्यवान और अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देना जारी रखेगा जिससे देश की विविध प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

इंडियाएआई के बारे में

इंडियाएआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग इंडियाएआई मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी है। यह समाज के सभी वर्गों में एआई के लाभों का लोकतांत्रिकरण करने, एआई में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने, तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और एआई के नैतिक और ज़िम्मेदारीपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र प्रथम के भाव को उजागर करने वाली एक अद्वितीय प्रस्तुति 'मेरा देश पहले'गुजरात में पहली बार 10 अक्टूबर को गिफ्ट सिटी में आयोजित होगी

गांधीनगर, 07 अक्टूबर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आकार ले रहे नए भारत के रूपांतरण की एक अनोखी कहानी 'मेरा देश पहले' का गुजरात में पहला शो शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में आयोजित होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है। उनके पूरे जीवन की अनेक घटनाएं और अवसर देशवासियों में देश प्रेम, समर्पण और राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत करने के लिए प्रेरणादायी बनी हैं। 'मेरा देश पहले'श्री नरेन्द्र मोदी के एक अद्वितीय सफर को मेगा शो के माध्यम से जीवंत करता है।

उल्लेखनीय है कि देश के अन्य राज्यों में 'मेरा देश पहले'के सफल और प्रशंसनीय मंचन के बाद, गुजरात में पहली बार गिफ्ट सिटी परिसर में यह शो निःशुल्क प्रवेश के साथ आयोजित होने जा रहा है।

शुक्रवार, 10 अक्टूबर को शाम 6.00 बजे गिफ्ट सिटी में आयोजित होने वाले इस शो को देखने के लिए केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ही निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है। इसके लिए www.giftgujarat.im पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

सुप्रसिद्ध कलाकार श्री मनोज मुंतशिर की प्रस्तुति 'मेरा देश पहले'का मंचन देखने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और मंत्रियों के साथ-साथ कई सामाजिक अग्रणियों को भी आमंत्रण दिया गया है।

नैतिकता, विरासत और आधुनिक एआई विजन को एकजुट करता भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो

भारत-एआई इम्पैक्ट समिट के विजेता लोगो डिजाइन में अशोक चक्र अंकित है, जो नैतिक शासन, न्याय, संवैधानिक मूल्यों और उत्तरदायी एआई नवोन्मेषण में भारत के नेतृत्व का प्रतीक है

(जीएनएस)।

भारत सरकार ने हाल ही में भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लोगो का अनावरण किया, जो 19-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा।

समिट के लिए लोगो का चयन मायगॉव प्लेटफॉर्म पर 28 मई से 12 जून 2025 तक आयोजित लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था। अंतिम प्रविष्टियों की समीक्षा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत उभरती प्रौद्योगिकी टीम द्वारा की गई, जिसने विजेता चयन प्रक्रिया का संचालन किया। मायगॉव को कुल 599 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिनमें से विजेता डिजाइन श्री अजित पी. सुरेश द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

विजेता डिजाइन मानवता की भलाई के लिए उत्तरदायी एआई नवोन्मेषण पर वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व करने की भारत की महत्वाकांक्षा को दशार्ता है। इसके केंद्र में अशोक चक्र है, जो नैतिक शासन, न्याय और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है जो भारत की डिजिटल यात्रा को आधार प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा, " मैंने लोगो का पहला संस्करण केवल 23 घंटों में डिजाइन किया, फिर एआई की नैतिकता को मूर्त रूप देने के लिए इसे परिष्कृत करता रहा - इसकी दीप्तिमान चमक भारत के विश्वव्यापी विजन का प्रतीक हैं। "

बाहर की ओर प्रज्जवलित, न्यूरल नेटवर्क फ्लेयर्स एआई की रूपांतरकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समावेशी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए भाषाओं, क्षेत्रों, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में व्याप्त विभाजन को पाटते हैं।

लोगो में सन्निहित प्रतीकवाद परंपरा (अशोक चक्र), नवाचार (तंत्रिका नेटवर्क फ्लेयर्स), विविधता (रंग ढाल) और स्पष्टता (टाइपोग्राफी) के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे समिट के विजन और मूल्यों को संप्रेषित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

लोगो में व्याप्त जीवंत अनुपात नवाचार और समावेशिता का प्रतीक है, जो एआई क्रांति का हिस्सा बनने वाले विविध उद्योगों, संस्कृतियों और समुदायों को दशार्ता है। रंगों का यह स्पेक्ट्रम अशोक चक्र द्वारा दर्शाए गए मूल्यों में निहित है।

इस प्रतीकात्मकता के पूरक के रूप में, स्वच्छ और आधुनिक टाइपोग्राफी स्पष्टता और विश्वास प्रदान करती है, जिससे डिजिटल और प्रिंट प्लेटफार्मों पर मजबूत स्मरण क्षमता और प्रासंगिकता सुनिश्चित होती है।

यह दृश्य पहचान परंपरा को आधुनिकता से, नैतिकता को नवाचार से और भारत की राष्ट्रीय पहचान को उसकी वैश्विक आकांक्षाओं से सहजता से जोड़ती है, जो भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की भावना को दशार्ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित, यह वैश्विक मंच समावेशी विकास, स्थिरता और समतामूलक प्रगति को बढ़ावा देने में एआई की परिवर्तनकारी भूमिका को प्रदर्शित करेगा। यह समिट एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जहां एआई मानवता की सेवा करता है, समावेशी विकास को आगे बढ़ाता है, सामाजिक विकास को प्रेरित करता है और ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देता है जो पृथ्वी की रक्षा करते हैं।

युद्ध का मैदान बदल गया है, भविष्य के युद्ध एल्गोरिदम, ऑटोनॉमस सिस्टम और एआई से लड़े जाएंगे; ड्रोन, एंटी-ड्रोन सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटिंग और निर्देशित-ऊर्जा हथियार भविष्य को परिभाषित करेंगेः रक्षा मंत्री

रक्षा पूंजी अधिग्रहण वित्त वर्ष 2021-22 में 74,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 1.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, यह केवल सांख्यिकीय परिवर्तन नहीं, बल्कि निर्भरता से आत्मविश्वास की मानसिकता में बदलाव है

आईडेक्स नवप्रवर्तकों से भारत का पहला रक्षा यूनिकॉर्न बनाने की अपील, युवाओं से भारत के प्रौद्योगिकीय परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह

आप एक ऐसे नए भारत के निमार्ता हैं जो अपने लिए डिजाइन, विकास और उत्पादन में विश्वास रखता है, आपके द्वारा लाई गई ऊर्जा और नवोन्मेषण प्रौद्योगिकीय रूप से आत्मनिर्भर भारत की कुंजी हैंः रक्षा मंत्री

आज 650 से अधिक आईडेक्स विजेता उभरे हैं और 3,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रोटोटाइप की खरीद सुनिश्चित की गई है, यह भारत के रक्षा नवोन्मेषण परिदृश्य में एक क्रांति का प्रतीक है

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 7 अक्टूबर, 2025 को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन से पहले 'रक्षा नवाचार संवादः आईडेक्स स्टार्टअप्स के साथ परस्पर संवाद' के दौरान कहा "युद्ध का मैदान बदल गया है। भविष्य के युद्ध एल्गोरिदम, ऑटोनॉमस सिस्टम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लड़े जाएंगे। ड्रोन, एंटी-ड्रोन सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटिंग और निर्देशित-ऊर्जा हथियार भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी ऐसा ही एक प्रदर्शन देखा है,"। उन्होंने नवप्रवर्तकों से विद्यमान समाधानों से आगे सोचने और युद्ध को नई परिभाषा देने वाली प्रोद्योगिकियों का विकास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हमें प्रौद्योगिकी में न तो नकलची बनना है और न ही अनुयायी, बल्कि हमें विश्व के लिए सृजक और मानक-निर्धारक बनना है।"

स्वदेशीकरण में उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घरेलू स्रोतों से रक्षा पूंजी अधिग्रहण 2021-22 में 74,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने इस बदलाव को "केवल एक सांख्यिकीय परिवर्तन नहीं, बल्कि निर्भरता से आत्मविश्वास की ओर मानसिकता में बदलाव" बताया। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत, वार्षिक खरीद का कम से कम 25 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए आरक्षित है और 350 से अधिक वस्तुएं विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित की गई हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, "रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता एक नारे से आगे बढ़कर एक आंदोलन बन गई है। नीति से व्यवहार तक और नवाचार से प्रभाव तक, यह परिवर्तन हमारे नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा संभव बनाया गया है।"

श्री राजनाथ सिंह ने स्टार्टअप्स को ऊंचे मानक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत में आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं, लेकिन रक्षा क्षेत्र में एक भी नहीं है। उन्होंने स्टार्टअप्स से इस स्थिति को बदलने का आ'ान किया। उन्होंने कहा, "भारत का पहला रक्षा यूनिकॉर्न आपके बीच से निकलना चाहिए। यह न केवल आपके लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी।" उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन को दोहराया कि सरकार नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और विचार से लेकर कार्यान्वयन तक हर कदम पर उनके साथ रहेगी।

रक्षा मंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन और 23,000 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात में रिकॉर्ड-तोड़ उपलब्धियों में योगदान देने वाले नवप्रवर्तकों के सामूहिक प्रयास की सराहना की।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से ₹10,907 करोड़ के 5 लाख से अधिक ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए

योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए सह-आवेदकों को शामिल करने, क्षमता-आधारित सीमा हटाने जैसे कई सुधार किए गए

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) ने स्वच्छ और सस्ती सौर ऊर्जा से घरों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने सितंबर 2025 तक ₹10,907 करोड़ की राशि के 5.79 लाख से अधिक ऋण आवेदनों को स्वीकृति दी जिससे घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि हुई है।

स्रोतः जनसमर्थ पोर्टल

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के कार्यान्वयन को ऋण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके, कम ब्याज दरों पर जमानत से मुक्त सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान करके और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से सरलीकृत वित्तपोषण के माध्यम से सक्रिय रूप से समर्थन दिया जा रहा है। इस सिलसिले में ऋण देने की प्रक्रिया जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाती है जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के राष्ट्रीय पोर्टल (स्रे२४१८ॅ१.ॅड्ढ५.ल्ल) के साथ जुड़ा

हुआ है। इससे लाभार्थियों के लिए निर्बाध डिजिटल आवेदन प्रक्रिया, बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

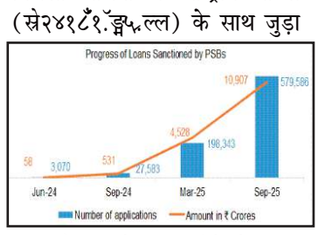

इस आदर्श ऋण योजना में जो प्रमुख लाभ शामिल हैं उनमें बिना किसी संपत्ति संबंधी जमानत के प्रतिस्पर्धी ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का ऋण, बिजली की लागत बचत के अनुरूप पुनर्भुगतान के लिए लंबी अवधि, भुगतान से 6 महीने की स्थगन अवधि, आवेदक की ओर से कम अंतर पर योगदान और स्वयं-घोषणा के आधार पर डिजिटल स्वीकृति प्रक्रिया शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सक्रिय भागीदारी से ऋण देने की प्रक्रिया को आसान बनाने और योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। उपयोगकताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर ऋण योजना में उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं जिनमें पात्रता का दायरा बढ़ाने के लिए सह-आवेदकों को जोड़ना, क्षमता-आधारित सीमाएं हटाना और दस्तावेज संबंधी आवश्यकताओं को सरल बनाना शामिल हैं।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के समन्वय से वित्तीय सेवा विभाग इस योजना के अंतर्गत ऋणों की प्रगति की सक्रिय रूप से समीक्षा करता है और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों के साथ सहयोग के माध्यम से इसके कार्यान्वयन को मजबूत करता है जिससे योजना को तेजी से अपनाया जा सके, इसकी बेहतर पहुंच हो और इसका व्यापक रूप से प्रसार हो सके।